कृपया प्रकाशनार्थ - **27 जुलाई 2009**

मछुआरों की माँगे प्रधानमंत्री पुरी करें : राम नाईक, प्रकाश जावडेकर

मुंबई, सोमवार : मछुआरों को फिर से डिजल पर रियायत मिले तथा उन्हें भी किसानों की तरह कम व्याज दर से कर्जा मिले ऐसी माँग भाजपा नेता श्री राम नाईक तथा सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से की है.

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्री राम नाईक ने कहा, "डिजल के बढते दामों को देखते हुए मछुआरों को डिजल पर मिलनेवाली रियायत भी बढा कर देनी चाहीए ऐसी माँग मछुआरे पिछले दो वर्षों से केंद्रिय कृषि मंत्री श्री. शरद पवार से कर रहें है. फिर भी समस्या का समाधान न होने से सांसद श्री प्रकाश जावडेकर के साथ मैंने यह मुद्दा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के पास उठाया."

मछुआरी नावों के लिए लगनेवाले डिजल पर रियायत देने की माँग सबसे पहले 1990 में श्री राम नाईक ने उठायी थी. जिसके अनुसार तत्कालीन वित्तमंत्री प्रा. मधु दंडवते ने प्रति लीटर 35 पैसे रियायत देने का निर्णय लिया. बाद में वाजपेयी सरकार में जब श्री राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे तब यह रियायत रु. 1.50 प्रति लीटर तक बढायी गयी. अब तो डिजल काफी महंगा हुआ है. इसलिए यह रियायत प्रति लीटर रु. 4/- होनी चाहिए इस माँग को लकर मछुआरों के संगठन के प्रतिनिधीओं के साथ श्री राम नाईक ने पिछले दो वर्षों में कई बार श्री शरद पवार से चर्चा की. कृषि मंत्री ने रियायत रु. 3 तक बढायी किन्तु नए निर्णय से उन्होने यह रियायत सिर्फ गरीबी रेषा के नीचे के मछुआरों को देने का फैसला किया. इससे मछुआरे काफी नाराज हुए है. "क्या गरीबी रेषा के नीचे के मछुआरे के पास लाखो रुपैयों की डिजल पर चलनेवाली बोट हो सकती है ?" ऐसा सवाल श्री राम नाईक व श्री प्रकाश जावडेकर ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से किया है. "कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने मछुआरों की समस्याएं हल नहीं की है इसलिए हम अब आपके पास आए हैं," ऐसा भी श्री नाईक व श्री जावडेकर ने अपने आवेदन में कहा.

पिछले सप्ताह मे प्रधान मंत्री से किए आवेदन में श्री नाईक व श्री जावडेकर ने कहा कि जो बात डिजल रियायत की वही मछुआरों को मिलने वाले कर्जे की. "मछुआरी को भी कृषि खेती माना जाता है. इसलिए किसानों की तरह मछुआरों के कर्ज भी माफ होने चाहिए तथा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम से (एनसीडीसी) से उन्हे भी 4 प्रति शत से कर्जा मिलना चाहीए इस माँग को भी कृषि मंत्री ने नजरअंदाज किया है. इस माँग पर भी प्रधानमंत्री गौर कर मछुआरों को न्याय दे, ऐसी माँग भी हमने की है," ऐसा भी दोनों ने कहा है.

(कार्यालय मंत्री)